

SHRI A. D. MANI: Has the attention of the Minister been drawn to an article by Mr. Ian McLeod, a former member of the British Cabinet in the British press suggesting that the privileges of Members of Parliament are not required at the present time, as these privileges were given to Members of Parliament during the historic period when the King wanted to suppress the House of Commons. What are the reactions of Government to the suggestion made by Mr. McLeod?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA: I am sorry I have not had the opportunity of reading that article. If the hon. Member sends it to me, I would give him my own reactions after that.

*726. [The questioner (Shri Niranjana Singh) was absent. For answer, vide col. 4787 infra.]

गोदियों में मासिक तथा रिजर्व
पूल मजदूर

*727. श्री राम सहाय : क्या श्रम तथा सेवा नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही प्रकार का कार्य करने वाले गोदी श्रमिकों को दो श्रेणियों अर्थात् मासिक तथा रिजर्व पूल मजदूरों की बजाय एक ही श्रेणी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो उसके कारण क्या हैं ?

[MONTHLY AND RESERVE POOL WORKERS IN
DOCKS

*727. SHRI RAM SAHAJ: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to have only one category of workers

instead of two categories viz., Monthly and Reserve Pool workers of dock workers doing the same type of work; and

(b) if the answer to part (a) above be in negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI D. SANJI-VAYYA):

(a) No.

(b) Employment in docks being of a fluctuating nature depending to a great extent on the arrival and departure of ships, traffic handled, etc., the object of the Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes is to provide regular employment to as large a number of workers as possible. Keeping the normal and future requirements in view, the continuance of both Monthly and Reserve Pool workers side by side is inevitable.

[श्रम तथा सेवा नियोजन मंत्री (श्री डी० संजीवैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) गोदियों में रोजगार घटता और बढ़ता रहता है क्योंकि यह अधिकतर जहाजों के आने और जाने, यातायात, आदि पर निर्भर करता है । इसलिए गोदी श्रमिक (रोजगार का विनियमन) योजनाओं का उद्देश्य यथासम्भव मजदूरों के लिए नियमित रोजगार की व्यवस्था करना है । सामान्य और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों की दोनों श्रेणियों अर्थात् मासिक और रिजर्व पूल मजदूरों का साथ साथ जारी रहना अनिवार्य है ।]

श्री राम सहाय : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकूंगा कि उनकी मजदूरी में और वर्किंग आवर्स में, काम करने के समय में, क्या कोई अन्तर है या एक से ही हैं ?

श्री रतनलाल किशोरी लाल मालवीय : महोदय, इन दोनों कैटेगरीज में काम के घंटों में तो कोई अन्तर नहीं है मगर वेतन में, मजदूरी में, जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ता है ।

दरअसल में जो स्कीम है उसमें कोशिश यह है कि जितने हमारे रिजर्व पूल के वर्कर्स हैं उनको हम परमानेन्टली या मन्थली बेसिस पर बना दें और वह कोशिश हमेशा जारी रहती है—बातें करते रहते हैं, ट्रिपार्टीट कमेटीज वगैरह में ये बातें होती हैं ।

श्री राम सहाय : उनकी मजदूरी में क्या अन्तर है ?

श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय : यह तो नहीं कह सकता हूँ कि कितने रुपये का फर्क पड़ता है मगर ऐसा होता है कि जो रिजर्व पूल वाले हैं उनको कुछ गारन्टी है कि जितने दिन काम करते हैं उसका मिलता है । वैसे मन्थली वर्कर्स को पूरे महीने के काम की तनख्वाह मिलती है ।

श्री राम सहाय : क्या इसकी कोई जाँच की है कि जो इस प्रकार के वर्कर्स हैं उनकी और जो मन्थली बेजिज पर काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह में कितना अन्तर पड़ता है ?

श्री रतनलाल किशोरीलाल मालवीय : मैं इस वक्त तो नहीं बता सकूँगा कि कितना फर्क पड़ता है । अलग-अलग कैटेगरीज के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गारन्टी दी जाती और उनके लिये इन्सेन्टिव्ह स्कीम लागू है और मैं समझता हूँ शायद वे लोग मन्थली से भी ज्यादा अर्न करते होंगे ।

MAIL MOTOR SERVICE IN POONA

•728. SHRI M. M. DHARIA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Mail Motor Service in Poona City has been taken over by P. & T. Department from Silver Jubilee Motors Pvt. Ltd.; and

(b) if so, how many drivers were working with the old operator and how many of them have been absorbed by the Department?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI B. BHAGAVATI): (a) Yes.

(b) Nine. None have been absorbed by the Department.

SHRI M. M. DHARIA: May we know the reason why the drivers working with the private operators have not been absorbed by the Department?

SHRI B. BHAGAVATI: On the termination of the contract, these drivers were employed temporarily as a stop-gap arrangement, but when the Department acquired the motor vehicles and made permanent arrangements, these drivers could not be retained, as they did not fulfil the basic conditions prescribed for recruitment of drivers in the Department.

SHRI M. M. DHARIA: What are the basic conditions, because in this case the drivers were working with the private operator and naturally when it was taken over by the Government, was it not their duty to take over these drivers as well? These poor drivers are now without any job. Now, they are more than 25 or 31, whatever it is and they cannot be employed anywhere else. May we know what are those basic conditions and reasons?

SHRI B. BHAGAVATI: The basic conditions are: firstly, age and secondly educational qualification. For recruitment of drivers these conditions have to be fulfilled. We have no obligation to employ them as they were employees under private contractors. The contract was terminated. This must not be confused with nationalisation of industries.

شہر پونا : عام طور پر یہ اصول رہا ہے گورنمنٹ کا کسی بھی سروس کو یا روٹ کو نیشنلائز کیا جاتا ہے یا کسی بھی دوسرے ادارے کو